

सुशासन दिवस

विशेषांक

वर्ष : 1, अंक : 6 | 25 दिसंबर, 2019





पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल में देश को सुशासन प्रदान किया। उन्होंने जनाकांक्षाओं पर खरा उतरने, विकास को सर्वस्पर्शी और समन्वयवादी बनाने का संदेश दिया और साथ ही देश के सामने सुशासन की एक नई तस्वीर पेश की।

जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली, तो उन्होंने अटल जी के सुशासन को जारी रखा और उसे मजबूती दी। पीएम मोदी ने कई ऐतिहासिक कदम उठाकर देश और दुनिया के सामने सुशासन की मिसाल पेश की। पीएम मोदी ने सुशासन को राजनीति का केंद्रबिंदु बनाया, जो उनकी पहली बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने गरीबी उन्मूलन और समाज के समुचित विकास के लिए जहां जन कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया, वहीं इन योजनाओं का समुचित लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए शासन की प्रक्रियाओं में सुधार के साथ ही डिजिटल इंडिया को माध्यम बनाया।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सुशासन की जो धारणा विकसित की, उससे देश की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई। देश आज सुशासन को ही शासन में आने की कसौटी मान रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का दोबारा केंद्र की सत्ता में आना उनकी सुशासन की नीतियों के प्रति जन समर्थन ही कहा जाएगा। आज 25 दिसंबर को जब पूरा देश अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है, तो यह उल्लेख करना जरूरी है कि पीएम मोदी किस तरह देश को सुशासन की राह पर तेजी से ले जा रहे हैं।



प्रगति की कुंजी सुशासन



“सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है। आम लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए काम करने वाली हमारी सरकार एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।”

“नागरिक-पहले” हमारा मंत्र, हमारा ध्येय और हमारा सिद्धांत है। सरकार को नागरिकों के करीब लाना मेरा सपना रहा है, ताकि वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।”



“सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्यधारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल बिहारी वाजपेयी का आभारी रहेगा।”



मोदी राज में 'अटल' सपने पूरे

- कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाने का हुआ फैसला
- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित करने की हुई घोषणा
- देश के सभी गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा गया
- मोदी राज में सभी गांवों तक बिजली पहुंची
- असम में रेल-रोड पुल बोगीबील का हुआ उद्घाटन
- 'केन-बेतवा लिंक' का काम मोदी सरकार ने किया पूरा
- सागरमाला कार्यक्रम के तहत 89 परियोजनाएं हुई पूरी

साकार होंगे सारे सपने



- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण की शुरुआत
- ग्रामीण इलाकों में होगा 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण
- मोदी राज में करीब 140 किलोमीटर रोजाना ग्रामीण सड़कों का निर्माण
- जनवरी 2020 तक दिल्ली - मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा पूरा
- रेल मंत्रालय द्वारा 21 बंदरगाह-रेल संपर्क परियोजनाओं पर काम शुरू
- भारतमाला के तहत 34,800 किमी हाइवे के निर्माण की योजना
- मोदी राज में राजमार्गों के निर्माण में आई तेजी
- मोदी राज में प्रतिदिन 30 किलोमीटर लंबे राजमार्गों का निर्माण
- 2018-19 में राजमार्गों का निर्माण और विस्तार 10,800 किमी तक पहुंचा
- 2013-14 की तुलना में ढाई गुना अधिक राजमार्गों का निर्माण
- आधारभूत संरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना
- रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही सुरंग का नाम 'अटल सुरंग' रखा गया
- लखनऊ में रखी गई अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधारशिला
- 2024 तक हर घर में जल पहुंचाने के लिए शुरू हुई अटल भूजल योजना

असरदार सरकार

- जन शिकायत को निपटाना पहली प्राथमिकता
- मांग के अनुरूप जीएसटी में हुआ सदा सुधार
- समय पर कार्यालय पहुंचने लगे हैं कर्मचारी
- जल्द से जल्द फाइलों को निपटाने पर जोर
- पीएमओ ने भ्रष्ट अधिकारियों की मांगी सूची
- पैसे के लिए फाइल दबाने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई
- बीते 5 सालों में 300 से अधिक भ्रष्ट अफसर सेवामुक्त
- 3 वर्षों से अहम पदों पर बैठे अधिकारियों के तबादले की रणनीति
- गैर-राजपत्रित पदों के लिए इंटरव्यू खत्म किया गया





- ➔ जन आंदोलन बना स्वच्छ भारत अभियान
- ➔ देश के सौ प्रतिशत घरों में शौचालय की सुविधा
- ➔ योग दिवस के आयोजनों में जन भागीदारी में वृद्धि
- ➔ फिट इंडिया अभियान को जन अभियान बनाने पर जोर
- ➔ 'मन की बात' कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधा संवाद
- ➔ सरकार और नागरिकों को करीब लाने का प्रयास
- ➔ mygov.in और interact with PM बना जनभागीदारी का मंच
- ➔ जन शिकायत निवारण तथा निगरानी प्रणाली का विकास



सबकी योजनाएं सबका विकास

- ➔ योजनाओं से गरीबों, वंचितों और आम लोगों का हुआ विकास
- ➔ जाति और धर्म के आधार पर लाभार्थियों से कोई भेदभाव नहीं
- ➔ जनधन योजना के तहत 37 करोड़ गरीब बैंकिंग सिस्टम से जुड़े
- ➔ उज्वला योजना से 8 करोड़ महिलाओं को मिला गैस कनेक्शन
- ➔ मुद्रा योजना से 21 करोड़ लोगों को बिना गारंटी मिला ऋण
- ➔ दलित-पिछड़े लोगों के स्वरोजगार के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना
- ➔ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
- ➔ फसल बीमा योजना के तहत 5.4 करोड़ किसानों का पंजीकरण
- ➔ हर बेघर को अपना पक्का घर देना संभव हो रहा है
- ➔ पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ नए घरों का निर्माण
- ➔ जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 6.4 करोड़ लोगों का नामांकन
- ➔ सुरक्षा बीमा योजना के तहत 17.02 करोड़ लोगों का नामांकन
- ➔ अटल पेंशन योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 1.85 करोड़



सबकी सेहत सबको राहत



- 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना
- 5 लाख रुपये के सालाना चिकित्सा बीमा की सुविधा
- योजना के तहत 70 लाख लोगों का हुआ इलाज
- जीवनोपयोगी दवाओं की कीमतों में आई भारी कमी
- कैंसर की दवाओं में 86 प्रतिशत तक की कमी
- मिशन 'इंद्रधनुष' के तहत 3.39 करोड़ बच्चों का टीकाकरण
- दवाओं की बिक्री के लिए 5,872 जन औषधि केंद्र खोले गए

व्यावहारिक कानून सरल प्रक्रियाएं

- पिछले पांच सालों में करीब 1450 कानून खत्म किए गए
- 'आधार' के माध्यम से गरीबों का हक हुआ सुनिश्चित
- एक पेज वाला सरल एमएसएमई पंजीकरण फॉर्म
- कंपनी अधिनियम के कई प्रावधान अपराध की श्रेणी से बाहर
- टैक्स सिस्टम में पारदर्शित, कुशलता और जवाबदेही लाने का प्रयास
- समय की मांग के मुताबिक श्रम कानूनों में बदलाव किए गए
- 32 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल बनाया गया
- हलफनामों और सत्यापनों की जगह स्व-सत्यापन का अधिकार



ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग भारत की रैंकिंग में अप्रत्याशित उछाल

79 स्थानों का उछाल



भ्रष्टाचार पर प्रहार



- ⌚ नोटबंदी सुशासन की दिशा में उठाया गया साहसिक कदम
- ⌚ बैंकों में कालाधन जमा करने वाले आयकर की राडार में आए
- ⌚ जीएसटी लागू होने से भ्रष्टाचार में आयी कमी
- ⌚ बेनामी संपत्ति लेन-देन रोकथाम कानून के तहत कार्रवाई तेज
- ⌚ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल, 2019 पारित
- ⌚ भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक-2018 के तहत रिश्वत पर रोक
- ⌚ भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत विदेश भागने वालों पर शिकंजा
- ⌚ इंसाॅल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड से बकाएदारों से कर्ज की वसूली
- ⌚ रियल एस्टेट सेक्टर में भ्रष्टाचार रोकने के लिए RERA लागू
- ⌚ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन
- ⌚ विदेशों में जमा संपत्ति के बराबर भारत में संपत्ति जब्त करने का प्रावधान

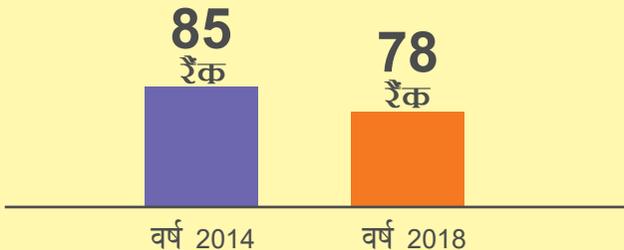
भ्रष्टाचार हुआ कम

वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, 2018 में भारत की रैंकिंग सुधरकर 78वें स्थान पर पहुंची, रिश्वतखोरी में 10 प्रतिशत की कमी

वैश्विक विश्वसनीयता सूचकांक में तीन अंक के सुधार के साथ भारत 52वें स्थान पर पहुंचा

वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक

भारत की रैंकिंग में सुधार



डिजिटल इंडिया से आसान हुआ जीवन



टेक्नोलॉजी से आई पारदर्शिता

- सरकार और नागरिकों के बीच खाई पाटने में सफल हुई टेक्नोलॉजी
- स्पेक्ट्रम की ऑनलाइन नीलामी से हुई करोड़ों की आमदनी
- 73 कोयला खदानों की नीलामी से मिले 3.44 लाख करोड़ रुपये
- निजी एफएम रेडियो चैनलों की हुई ऑनलाइन नीलामी
- यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 2.7 अरब पहुंची
- यूपीआई से कुल 4.6 ट्रिलियन रुपये का लेनदेन हुआ
- भीम ऐप से डिजिटल पेमेंट में अप्रत्याशित वृद्धि
- सरकारी विभागों में सामानों की ऑनलाइन खरीदारी
- दिल्ली की 1731 कॉलोनियों का नक्शा वेबसाइट पर अपडेट
- सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उपलब्ध
- डीबीटी के दायरे में 56 मंत्रालयों की 436 योजनाएं
- डीबीटी से 70.6 करोड़ लाभार्थियों को मिला फायदा
- 2019-20 के दौरान डीबीटी से 1.4 लाख करोड़ रुपये की बचत
- 20 सरकारी सेवाओं के लिए एकल खिड़की व्यवस्था
- वन और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया
- ईएसआईसी और ईपीएफओ के लिए ऑनलाइन पोर्टल
- ई-नाम पोर्टल पर 1.65 करोड़ किसानों का पंजीकरण
- जनवरी 2020 से लागू होगा इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयस

डिजिटल भुगतान में जबर्दस्त वृद्धि कीमत में यूपीआई लेन-देन



50 करोड़ रुपये

अक्टूबर 2016

4.6 ट्रिलियन रुपये

नवंबर 2019

महिला सशक्तीकरण



- समाज की सोच बदलने के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना
- बालिकाओं के सुनहरे और सुरक्षित भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना
- बालिका शिक्षा के प्रति समर्पित उड़ान (UDAAN) योजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की संख्या एक करोड़ पार
- सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका
- पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय
- पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी में हुई 53% की वृद्धि
- कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा कानून लागू किया गया
- मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया
- एसिड अटैक की पीड़िताओं को दिव्यांगों जैसी मदद दी गई
- महिलाओं को पासपोर्ट में शादी के पूर्व का उपनाम रखने की मिली छूट





अल्पसंख्यकों का विकास

- पीएम मोदी के अनुरोध पर सऊदी अरब ने हज कोट बढ़ाया।
- 2019 में रिकॉर्ड 2 लाख भारतीय मुसलमानों ने हज यात्रा की।
- बिना 'मेहरम' महिला के हज यात्रा पर जाने की रोक हटाई गई।
- 2019-20 में बजट बढ़कर 4700 करोड़ रुपये हो गया।
- पीएम जन विकास कार्यक्रमों का विस्तार 308 जिलों तक हुआ।
- अगले 5 साल में 5 करोड़ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां मिलेंगी।
- दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए 'हुनर हाट' का आयोजन।
- मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति मिली।
- विभिन्न भाषाओं में गुरुवाणी के प्रकाशन का फैसला किया गया।
- 2015 में सिखों को इंसाफ दिलाने के लिए एसआईटी बनाई गई।
- पीएम मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर देश को समर्पित किया।
- 2015 में बुद्ध जयंती को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
- "जियो पारसी" योजना से पारसी समुदाय के 184 बच्चों का जन्म हुआ।





दिव्यांगों का कल्याण

- 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' पारित किया गया
- दिव्यांगता से संबंधित सभी तरह के भेदभाव पर लगी रोक
- 7745 शिविरों से 12.3 लाख दिव्यांगों को लाभ पहुंचा
- दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 किया गया
- मनोचिकित्सा, फीजियोथेरेपी, सर्जिकल व स्पीच थेरेपी की सुविधा
- 416 विशेष कैंपों में सहायक यंत्रों और उपकरणों का वितरण



दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था



सुशासन
दिवस



- आईएमएफ ने भारत को विश्व का सबसे उभरता हुआ सितारा बताया।
- वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन के लिए तारीफ की।
- मोदी सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया।
- 2009-2014 के दौरान जीडीपी विकास दर 6.4 प्रतिशत रही, जबकि 2014-2019 के बीच यह 7.5 प्रतिशत रही।
- 2013-14 के दौरान महंगाई दर 10.3 प्रतिशत थी, जबकि 2018-19 के दौरान यह 4.5 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2014 में खाद्य महंगाई दर 11.2 प्रतिशत थी, जबकि 2019 में यह सिर्फ 3.5 प्रतिशत थी।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 454.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।
- मोदी सरकार ने न्यू इंडिया के लिए नया रोडमैप जारी किया और अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने पर जोर दिया।
- मोदी सरकार ने मैनुफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स की घोषणा की।
- दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा Start-Up Ecosystem भारत में मौजूद।





आंतरिक और बाह्य सुरक्षा

- देश में सुरक्षा का माहौल, बम विस्फोटों में आई कमी
- रक्षा सौदों में यूपीए सरकार के दौर में व्याप्त जड़ता हुई खत्म
- राफेल विमान से भारतीय वायु सेना को मिली मजबूती
- दूसरे देश से लाखों करोड़ के अस्त्र-शस्त्रों की खरीद हुई
- 'मेक इन इंडिया' के तहत भारत में अस्त्र-शस्त्र बनाने पर जोर
- दो सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सिखाया सबक
- चीन की सीमा तक सड़कों और रेल लाइनों का जाल बिछाने का काम
- चीन की सीमाओं पर ब्रम्होस मिसाइल और राफेल विमानों की तैनाती
- अमेरिका से रक्षा-संधि मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि

विश्व में बढ़ी साख और धाक

- पीएम मोदी की कोशिशों से दुनिया भर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है।
- पीएम मोदी ने अपने शपथ-ग्रहण समारोह में दक्षिण देशों के प्रमुखों को आमंत्रित किया।
- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है।
- मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय साजिशों को नाकाम किया।
- पीएम मोदी की कूटनीति ने पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग-थलग किया।
- जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या पर भारत नेतृत्व करने में सक्षम हुआ।

